E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2020; 2(3): 693-696
Received: 20-06-2020
Accepted: 22-07-2020

श्याम कुमार
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग)
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
श्याम कुमार
शोधार्थी (राजनीति विज्ञान विभाग)
ल0 ना0 मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा, बिहार, भारत

वैश्वीकरण, खुलापन और आर्थिक राष्ट्रवादः वैचारिक मुद्दे और एशियाई अभ्यास

श्याम कुमार

सारांश
यह पत्र आर्थिक खुलेपन के लेंस के माध्यम से आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रश्न पर विचार करता है। पूर्ण आर्थिक खुलापन, जो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश के घनिष्ठ या कुल एकीकरण को दर्शाता है, आर्थिक राष्ट्रवाद का एक उदाहरण है। आर्थिक खुलापन एक बहुआयामी अवधारणा है। एक देश खुला हो सकता है, किन्तु कुछ या सभी के लिए खुला नहीं हो सकता हैः व्यापार, निर्यात, आयात, वित्त, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा, प्रवासन, विदेशी निवेश, अपने नागरिकों और कंपनियों द्वारा निवेश, अन्य बातों के अलावा कोई आर्थिक सिद्धांत नहीं है जो बताता है कि एक देश को सभी आयामों में एक साथ खुला होना है। अपनी आर्थिक और भू–राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, एक देश कुछ क्षेत्रों में खुला होना चुन सकता है और अन्य में नहीं। पेपर विश्लेषणात्मक प्रश्न की जांच करता हैः अर्थव्यवस्था के लिए खुलेपन की इष्टतम डिग्री क्या है? इस सैद्धांतिक ढांचे का उपयोग एशियाई अनुभव को चित्रित करने और समझाने के लिए किया जाता है, विशेष रूप से जापान और कोरिया का। इन और अन्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ–साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नीति के निहितार्थ को रेखांकित किया गया है। कागज का मुख्य नीतिगत संदेश यह है कि देशों को, जब भी वे अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ एकीकरण के बजाय 'रणनीतिक' कर सकते हैं, उस अर्थ में, आर्थिक राष्ट्रवाद, वैश्वीकरण के बावजूद अभी भी कई एशियाई देशों में दिन का क्रम है। उन्हें अस्थिर पूंजी आंदोलनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण बनाए रखने और राष्ट्रीय हित में वित्तीय क्षेत्र को विवेकपूर्ण रूप से विनियमित करने की आवश्यकता है।

मुख्यशब्दः आर्थिक राष्ट्रवाद, खुलापन, सामरिक एकीकरण

प्रस्तावना
यह पत्र आर्थिक खुलेपन के लेंस के माध्यम से आर्थिक राष्ट्रवाद के प्रश्न पर विचार करता है। पूर्ण आर्थिक एकीकरण, जो विश्व अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश के घनिष्ठ या कुल एकीकरण को दर्शाता है, आर्थिक राष्ट्रवाद का एक उदाहरण है। आलेख का तर्क है कि आर्थिक खुलापन एक बहुआयामी अवधारणा है। एक देश खुला या इतना खुला नहीं हो सकता है, सभी या कुछ निम्न दिशाओं मेंः व्यापार, निर्यात, आयात, वित्त, विज्ञान, संस्कृति, शिक्षा, प्रवास, विदेशी निवेश, अपने नागरिकों और कंपनियों द्वारा विदेशों में निवेश, अन्य बातों के अलावा कोई आर्थिक सिद्धांत नहीं है जो बताता है कि एक देश को सभी आयामों में एक साथ खुला होना है। अपनी आर्थिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए, कोई देश कुछ क्षेत्रों में खुला होना पसंद कर सकता है, न कि केवल आंशिक रूप से या दूसरों में आंशिक रूप से। पेपर विश्लेषणात्मक प्रश्न की जांच करता हैः अर्थव्यवस्था के लिए खुलेपन की इष्टतम डिग्री क्या है? इस सैद्धांतिक ढांचे का उपयोग एशियाई अनुभव को चित्रित करने और समझाने के लिए किया जाता है, खासकर जापान और कोरिया के। इन और अन्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के साथ–साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए नीति के निहितार्थ को रेखांकित किया गया है। कागज का मुख्य नीतिगत संदेश यह है कि देशों को, जब भी वे चाहें, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के साथ 'घनिष्ठ' एकीकरण के बजाय 'रणनीतिक' कर सकते हैं।[1]

खुला और आर्थिक योजना का इष्टतम डिग्री
प्रिंसिपल में, दो खुले गैर–अनन्य तरीकों से खुलेपन की इष्टतम डिग्री को परिभाषित करने की समस्या से संपर्क कर सकते हैं। शुरू करने के लिए, एक स्पष्ट विधि राष्ट्रीय योजना के बारे में सिद्धांत का उपयोग करना है। इसमें अर्थव्यवस्था के लिए एक उपयुक्त मॉडल तैयार करना शामिल है जिसमें प्रासंगिक बाधाओं के साथ–साथ एक उपयुक्त सामाजिक वरीयता समारोह (या अधिक सामान्यतः, एक कार्यात्मक) के विनिर्देश शामिल होंगे। ये बाधाएं प्राथमिक रूप से बदलने के लिए अवसरों की मात्रा का ठहराव शामिल करेंगी उत्पादन या व्यापार के माध्यम से वांछित वस्तुओं में सीमाओं की स्थितियों को परिणाम देने के लिए डाला जा सकता है ताकि परिणाम अधिक से अधिक

यथार्थता प्राप्त कर सकें। 'खुलेपन की इष्टतम डिग्री', या इस पेपर में परिभाषित आर्थिक राष्ट्रवाद की अवधारणा, विवश अधिकतम अभ्यास के परिणाम के रूप में अनुसरण करेगी। विश्लेषण को स्थिर या गतिशील शब्दों में डाला जा सकता है। समाधान चरों में क्षेत्रों और साथ ही निर्यात और आयात द्वारा उत्पादन और / या निवेश स्तर शामिल हैं। उन्हें समय पथ के रूप में कहा जा सकता है यदि प्रासंगिक मॉडल एक समय–चरणबद्ध है।[2]

आमतौर पर इस तरह के अभ्यास वास्तविक रूप में किए जाते हैं और पूरक मौद्रिक परिमाण के सेट को अनिर्धारित किया जाता है। इन्हें आमतौर पर मैक्रो–इकनॉमिक मॉडल की मदद से तैयार किया जाता है। इस विषय पर काफी साहित्य है और अधिक शक्तिशाली कंप्यूटरों पर जटिल अनुकूलन मॉडल को संभालने की बढ़ती क्षमता के साथ, यह देर से पचास के दशक में चेनरी, ब्रूनो और कई अन्य लोगों द्वारा किए गए प्रारंभिक अभ्यासों की तुलना में कुछ सुधारों का कारण बना।

हालांकि, यह मानने के कई कारण हो सकते हैं कि दृष्टिकोण पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है। हालांकि एक नियोजन दृ ष्टिकोण से मुक्त व्यापार के शासन के साथ खुलेपन की इष्टतम डिग्री की आसान और सहज पहचान से बचता है, लेकिन यह कई सीमाओं से ग्रस्त है। सबसे पहले, एक स्केलर मैक्सिमम का पोस्टऑउट काफी अनुचित हो सकता है जब तक कि एकरूपता की डिग्री को भविष्य की पीढ़ियों तक नहीं बढ़ाया जाता है, न कि बहुत यथार्थवादी धारणा, इसे हल्के ढंग से डालने के लिए। दूसरे, विश्लेषण समय के साथ अपरिवर्तनीयता से जुड़े मुद्दों को ध्यान में नहीं रख सकता है।[3]

तीसरे, इतिहास के साथ इस दृष्टिकोण का एकमात्र संबंध प्राथमिक कारकों के वैक्टर के प्रारंभिक विनिर्देश के माध्यम से है, जो आसानी से मात्रात्मक हैं। बाहरी दुनिया से कारकों के प्रवाह को प्रासंगिक माना जाता है, तो समुदाय को ज्ञान की अवस्थाओं या इसकी अवशोषण क्षमता की मात्रा निर्धारित करने का कोई सरल और सुविधाजनक तरीका नहीं है।

चौथा, राष्ट्रीय नियोजन मॉडल किसी एक देश के लिए विवरण में समृद्ध हैं। हालाँकि, संचालन के लिए, सार्थक उन्हें यह मानना होगा कि बाकी दुनिया या तो स्थिर रहने वाली है या केवल पूर्वनिर्धारित तरीके से बदल सकती है। रणनीतिक विकल्पों को बाहर रखा गया है।[4]

विश्व अर्थव्यवस्था में संयुग्मित बदलावों से उत्पन्न होने वाले संरचनात्मक परिवर्तन भी मॉडल परिणामों से उतने तेज नहीं हो सकते हैं, जितने तेजी से होंगे। यदि कोई इन आलोचनाओं को गंभीरता से लेता है, तो नियोजन अभ्यास का विकल्प कुछ हद तक शिथिल होगा, लेकिन अधिक ऐतिहासिक रूप से जमीनी दृ ष्टिकोण, जो न केवल उन लाभों पर जोर देता है, जो एक राष्ट्रीय इकाई को बाकी के साथ व्यापार करने के अवसरों की तलाश करने की संभावना है। दुनिया लेकिन कुछ कारकों पर भी जोर देती है जो इसे बाहरी प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकते हैं। ये देश के उत्पादन के पैटर्न और उत्पादक रोजगार उत्पन्न करने की क्षमता आदि पर दीर्घकालिक अपरिवर्तनीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं।[5]

मुक्त व्यापार के लिए तर्क

कल्याणकारी अर्थशास्त्र के दो वि मूलभूत प्रमेयों 'का हवाला देकर जतंकम मुक्त व्यापार' की स्थिति के पक्ष में तर्क को एक कॉम्पैक्ट तरीके से कहा जा सकता है। ये प्रमेय वर्तमान प्रवचन के लिए प्रासंगिक हो जाते हैं यदि किसी को पता चलता है कि 'व्यापार' को उत्पादन का साधन माना जा सकता है। इस विश्लेषण के लिए इन प्रमेयों की प्रासंगिकता को सामने लाने के लिए, एरो और हैन (1971) को आगे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि कोई भी यह मान लेगा कि घरेलू कारक आपूर्ति को एक विशेष समूह की फर्मों के लिए 'निजी' कारकों के रूप में माना जा सकता है। यह वह उपकरण है जो वे सामान्य प्रतिस्पर्धी संतुलन विश्लेषण के दायरे में विदेशी व्यापार से संबंधित समस्याओं को संभालने के लिए नियोजित करते हैं। हमेशा की तरह कारक, एक नकारात्मक संकेत वाले उत्पादों के रूप में माना जा सकता है। पहले के अनुसार बाहरी और अनुपस्थिति के अभाव में एक प्रतिस्पर्धात्मक संतुलन, एक इष्टतम का गठन करता है। हालांकि, तथाकथित कन्वर्सेशन प्रमेय हमारे दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है, और बहुत अधिक कठोर मांग करता है। इस कन्वर्सेशन प्रमेय 'के अनुसार, अन्यथा कल्याणकारी अर्थशास्त्र के दूसरे प्रमेय के रूप में जाना जाता है।[6]

यदि ये धारणाएं पकड़ में आती हैं, तो दूसरा प्रमेय वास्तव में नियोजन के दृष्टिकोण से एक उपयोगी है। यदि अर्थव्यवस्था एक छोटी सी खुली है, और प्रतिस्पर्धी संतुलन दुनिया में बड़े पैमाने पर मौजूद है, तो, देश व्यापार के किसी भी प्रतिबंधित रूप की तुलना में मुक्त व्यापार से बेहतर है, अकेले स्वायत्तता दें। केवल जब देश विश्व बाजार में नीचे की ओर ढलान की मांग का सामना करने के लिए पर्याप्त बड़ा है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मुक्त व्यापार से विचलन के लिए पहला सबसे अच्छा तर्क है। यह 'इष्टतम टैरिफ', तर्क का सार है। हालाँकि, परिणाम केवल एक देश पर लागू होता है, जब शेष विश्व ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि वह निष्क्रिय था और एक रूप या अन्य में प्रतिशोध में नहीं लगा हुआ था। इस तर्क पर, अंतरराष्ट्रीय रूप से स्थिर कारकों की कमाई किराए की प्रकृति में है, अर्थात वे मूल्य–निर्धारित हैं। अनुचित मांग स्थितियों के तहत, घरेलू रूप से उपलब्ध अकुशल श्रम के मामले में, वे शून्य तक गिर सकते हैं। हालांकि, यह माना जाता है कि राष्ट्रीय प्राधिकारी उपयुक्त घरेलू प्रतिपूरक आय हस्तांतरण की व्यवस्था करके इस समस्या का ध्यान रख सकते हैं, जो वास्तव में एक लंबा आदेश है।[7]

मूल्य विकृतियाँ

हाल के प्रकाशनों में अपने अर्थमितीय विश्लेषण में बैंक अर्थशास्त्री खुलेपन की मात्रात्मक माप का उपयोग करते हैं– एक अर्थव्यवस्था में घरेलू कीमतें अंतर्राष्ट्रीय सापेक्ष कीमतों से भिन्न होती हैं। उस उपाय पर, यह पता चलता है कि जापान और कोरिया दोनों ही कम से कम खुली अर्थव्यवस्थाओं के बीच थे (चमत्कार अध्ययन, पृ .301)। ब्राजील, भारत, मैक्सिको, पाकिस्तान और वेनेजुएला की तुलना में इन देशों में सापेक्ष मूल्य अधिक विकृत थे, अक्सर ब्रेटन वुड्स संस्थानों द्वारा उन देशों के प्रमुख उदाहरणों के रूप में आयोजित किया जाता है जो 'कीमतों को सही नहीं पाते हैं'। जापान और कोरिया व्यापक रूप से कई विश्व बैंक रिपोर्टों के केंद्रीय शोध का खंडन करते हैं, जो अर्थव्यवस्था को जितना अधिक खोलते हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ उसके एकीकरण के करीब होंगे, उतनी ही तेजी से इसकी वृद्धि दर होगी। विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक गहन या बिना शर्त एकीकरण के बजाय तेजी से विकास की अपनी अवधि के दौरान, इन देशों ने स्पष्ट रूप से मांग की जिसे रणनीतिक एकीकरण कहा जा सकता है, अर्थात् वे इस बिंदु तक एकीकृत थे कि ऐसा करना उनके हित में था ताकि राष्ट्रीयता को बढ़ावा दिया जा सके। आर्थिक नीति के हस्तक्षेप के लिए ऐसा स्थान दुर्भाग्य से आज के विकासशील देशों के लिए बहुत कम उपलब्ध है।[8]

आर्थिक राष्ट्रवाद और मुक्त पूंजी प्रवाह

मुक्त व्यापार पर प्रतिबंध से अधिक, एशियाई देशों में आर्थिक राष्ट्रवाद आज यकीनन पूंजी के मुक्त आंदोलन पर सीमाओं के

माध्यम से ही प्रकट होता है। यह एक अत्यधिक विवादास्पद विषय है जहां विषमलैंगिक और रूढ़िवादी अर्थशास्त्रियों के बीच मजबूत असहमति है और जहां वास्तविक दुनिया में आर्थिक सिद्धांत और वास्तविक घटनाओं के बीच शायद सबसे बड़ा वियोग है। नियोक्लासिकल थ्योरी बताती है कि बाहरी पूंजी के प्रवाह को किसी देश के उपभोग या उत्पादन पथ को सुचारू बनाने में मदद करके संतुलन बनाना चाहिए। हालांकि, वास्तविक दुनिया में, ठीक इसके विपरीत प्रतीत होता है। पूंजी खाता 1990 के दशक में एशिया और लैटिन अमेरिका में गंभीर आर्थिक और वित्तीय संकटों से जुड़ा हुआ है। नव–शास्त्रीय सिद्धांत के समर्थकों का तर्क है कि मुक्त पूंजी प्रवाह के लिए मामला मुक्त व्यापार के लिए इससे अलग नहीं है। पूर्व को केवल अंतर–अस्थायी व्यापार के रूप में माना जा सकता है।[9]

एशियाई संकट और पूंजी खाता उदारीकरण

1990 के दशक के उत्तरार्ध का एशियाई संकट उस क्षेत्र की गंभीर आर्थिक मंदी के कारण या उसमें पूंजीगत उदारीकरण की भूमिका की जांच के लिए लगभग एक प्रयोगशाला प्रयोग प्रदान करता है। ड्रेबेक और विलियमसन (1999) ने यह सुझाव देने के लिए साक्ष्य प्रदान किए कि जिन देशों ने आर्थिक संकट किया था या नहीं थे, केवल उनके पूंजीगत खातों को उदार बनाया था या नहीं, इससे अलग थे। अधिकांश अर्थशास्त्री अब इस बात से सहमत होंगे कि पर्याप्त विवेकपूर्ण नियमन के बिना समय से पहले वित्तीय उदारीकरण थाईलैंड, कोरिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में संकटों का मूल कारण नहीं था, लेकिन इसने संकट की घटना और इसकी गहराई में योगदान दिया। वास्तव में, प्रभावित देशों के संकट से पहले के आर्थिक बुनियादी ढांचे भारत की तुलना में बेहतर थे, लेकिन बाद वाले देश ने पूंजी खाते पर नियंत्रण के कारण संकट को बख्शा था। इसी तरह, चीन संकट से बचने में कामयाब रहा और तेजी से आर्थिक विकास जारी रखा। चीन के पास भी आंशिक रूप से ही सही लेकिन अपने पूंजी खाते का पूरी तरह से उदारीकरण था।[10]

यह कुछ लोगों द्वारा तर्क दिया जाता है कि, 1998–1999 के तीव्र आर्थिक संकट के साथ, कोरिया अपनी आर्थिक खुलेपन के साथ भारत की तुलना में लंबे समय से अधिक सफल अर्थव्यवस्था था। इस तर्क की कुछ प्रशंसनीयता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज करता है कि पिछले तीन दशकों में कोरिया का उत्कृष्ट औद्योगिकीकरण रिकॉर्ड उदारीकृत वित्तीय प्रणाली के साथ नहीं था, बल्कि एक उच्च नियंत्रित द्वारा था। हालाँकि, जब 1990 के दशक में इस प्रणाली का उदारीकरण किया गया था, तब यह एक अभूतपूर्व संकट (डेमेट्रियड्स और लुइंटेल, 2001) द्वारा पीछा किया गया था।

सिंह (2002) और एरेस्टिस और सिंह (2010 आगामी) पूंजी खाता उदारीकरण, पूंजी प्रवाह, विकासशील देशों में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि और इसकी अस्थिरता पर अनुभवजन्य साक्ष्य की सारांश समीक्षा प्रदान करते हैं।[11] समीक्षा बताती है कि उदारीकरण और आर्थिक और वित्तीय संकटों के बीच घनिष्ठ और मजबूत संबंध है। विकासशील देशों की परिस्थितियों में इसके अस्तित्व और मजबूती दोनों के लिए मजबूत विश्लेषणात्मक तर्क भी हैं। दूसरी ओर, उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत नहीं देते हैं कि मुक्त पूंजी प्रवाह ठेठ विकासशील देश के लिए तेजी से दीर्घकालिक आर्थिक विकास का कारण बनता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, स्टिग्लिट्ज़ (2000) पूंजी खाता उदारीकरण को बढ़ावा देने के लिए आईएमएफ की अपनी आलोचना में पूरी तरह से उचित है। इतना ही नहीं पूंजी खाते के उदारीकरण के ऐसे जासूसी के लिए कोई पर्याप्त सैद्धांतिक या अनुभवजन्य मामला नहीं है, वास्तव में इसके खिलाफ एक मजबूत मामला है। दरअसल आर्थिक संकट और अस्थिरता जो पूंजी खाते के उदारीकरण को उत्पन्न करने के लिए देखी जाती है, वह पूंजी उड़ान को प्रेरित करके और घरेलू निवेश और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को कम करके देश के भविष्य के आर्थिक विकास से समझौता कर सकती है।[12]

निष्कर्ष

आर्थिक राष्ट्रवाद, हमने पहले व्यापार खुलेपन की हमारी चर्चा में देखा है, सबसे उपयोगी है जब विश्व अर्थव्यवस्था धीरे–धीरे बढ़ रही है और गतिशील विकास की संभावना कम है। कुछ अवसरों पर जब विश्व अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है या तेजी से बढ़ने की संभावना है (तकनीकी प्रगति के लिए उदाहरण के लिए) आर्थिक राष्ट्रवाद का पीछा करना एक महंगी गलती हो सकती है। हालाँकि, जहां तक पूंजी के मुक्त प्रवाह का संबंध है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को नुकसान को रोकने के लिए आर्थिक राष्ट्रवाद सामान्य रूप से एक शक्तिशाली हथियार होने की संभावना है। जब आर्थिक राष्ट्रवाद पूँजी प्रवाह के संबंध में होता है, तो अपेक्षाकृत कुछ कमज़ोर होते हैं, जो विकासशील देशों की तुलना में अच्छा हो सकता है। इस संदर्भ में, 1990 के दशक के उत्तरार्ध के एशियाई संकट के जवाब में आर्थिक राष्ट्रवाद ने जो रूप धारण किया है, उसका पालन करना महत्वपूर्ण है। पूँजी प्रवाह की वजह से होने वाली अपार कठिनाइयों, या एशियाई संकट के दौरान इनकी कमी के मद्देनजर, किसी ने एशियाई देशों से मुक्त पूँजी आंदोलनों के स्थान पर पूँजी नियंत्रण के शासन की अपेक्षा की होगी। हालांकि, मलेशिया के अलावा, अधिकांश देशों ने वित्तीय या पूंजीगत खाते के उदारीकरण को नहीं छोड़ा। ज्यादातर मामलों में, वे नहीं बढ़े लेकिन न तो उन्होंने इसे काफी कम किया। इसके बजाय, उन्होंने चालू खाता अधिशेष के माध्यम से भंडार का निर्माण करके अवांछित पूंजी आंदोलनों के खिलाफ खुद का बचाव करने का विकल्प चुना। वर्तमान वैश्विक वित्तीय संकट के दौरान विकासशील देशों के लिए इस तरह का आर्थिक राष्ट्रवाद सबसे उपयोगी साबित हुआ हैः संकट के नकारात्मक प्रभाव को कम करने और अन्य देशों की तुलना में तेजी से उबरने के लिए अधिशेष और आरक्षित संचय कई देशों के लिए मददगार रहे हैं।

अंत में, वैश्वीकरण के तहत भी आर्थिक राष्ट्रवाद एक उपयोगी अवधारणा है लेकिन इसके व्यावहारिक नीति अनुप्रयोग के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक रुझानों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण आवश्यक है।

संदर्भ

1. आनंद, एस. और जोशी, वी. घरेलू विकृतियाँ, आय वितरण और इष्टतम सब्सिडी का सिद्धांत 'आर्थिक पत्रिका 1979;(89):336-352।
2. तीर, के.जे. और हैन, एफ.एच. जनरल कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, होल्डनडे, सैन फ्रांसिस्को 1971।
3. डेमेट्रियड्स, पी.ओ. और लुइंटेल, केबी दक्षिण कोरियाई चमत्कार में वित्तीय प्रतिबंध, जर्नल ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स 2001;64(2):459-479।
4. मेजेज़िनर, आई. और टी. हाउट, शॉर्ट–टर्मिज्म ऑन ट्रायल, (लंदनः इंस्टीट्यूशनल फंड मैनजेट एसोसिएशन) 1980।
5. फेलिक्स, डी. पूर्वी एशिया में औद्योगिक विकासः लैटिन अमेरिका के लिए क्या सबक हैं?, अंकटाड चर्चा पत्र, संख्या 4, मई 1994 ।
6. गेलिन, ए. ह्यूजेस, ए. लिपिट्ज़, ए. और सिंह, ए. 'द राइज एंड फॉल ऑफ द गोल्डन एज' मार्ग्लिन, एस.ए. और श्योर, जे. (एड.), द गोल्डन एज ऑफ कैपिटलिज्म, ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस 1992।

7. हिर्शमैन, ए.ओ. ए बायस फॉर होप, येल यूनिवर्सिटी प्रेस 1971, 228–229।
8. क्रुगमैन, पी. आर. चें इज़ फ्री ट्रेड पास? 'जर्नल ऑफ़ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स, फॉल 1987;1(2):131-143।
9. मार्शल, ए. आधिकारिक कागजात, मैकमिलन एंड कंपनी, लंदन 1926।
10. समर्स, एल., 'अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकटः कारण, निवारण और इलाज।' अमेरिकी अर्थशास्त्र समीक्षा पत्र और कार्यवाही 2000;90(2):1-16।
11. वेड, आर. मार्केट गवर्निंगः इकोनॉमिक थ्योरी और ईस्ट एशियन इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रिंसटन प्रेस में सरकार की भूमिका 1990।
12. पी. क्रुगमैन (सं.), रणनीतिक व्यापार नीति और नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र (कैम्ब्रिज एमएः द एमआईटी प्रेस) में यममुरा, के. कैविट एम्प्टरः जापान की औद्योगिक नीति' 1988।